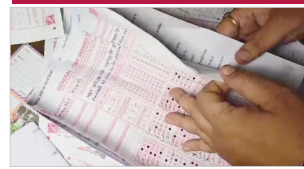


मुस्लिम नाबालिग की शादी करना सही है या गलत, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

संक्षिप्त समाचार



सिपाही मर्ती परीक्षा: फर्जी आंसर शीट मिली, मास्टरमाइंड समेत दस गिरफ्तार

पटना। बिहार में 38 जिलों में 5.45 करोड़ रुपये पर पुलिस सिपाही मर्ती परीक्षा जारी है। करीब 18 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हैं। परीक्षा 7 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा से पहले खड़ागंजी में फर्जी आंसर शीट और पेपर मिले हैं। मंगलवार देर रात पुलिस ने खड़ागंजी कर सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड समेत दस लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जानकारी मिली कि सॉल्वर गैंग के 90 छात्रों को एक मैरिज हॉल में इकट्ठा कर आमोआर शीट पर पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है। मास्टरमाइंड परबता प्रखंड के नयागंज कारागार में रखा है। आरोपी दिवाकर कुमार ने परीक्षार्थियों से एक-एक लाख रुपये लिए हैं। सभी छात्रों को पेपर देने की बात कही गई थी। पुलिस ने मैरिज हॉल से पकड़े गए सभी परीक्षार्थियों का सत्यापन कर परीक्षा में शामिल होने के लिए छेड़ दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस को मक के पर से परीक्षा से जुड़े फर्जी आमोआर शीट सहित कई पेपर भी मिले हैं। पटना के टीपीएस कॉलेज के पास गली में कुछ अस्थायी मोबाइल से देखकर पची पर कुछ नोट नजर आए। हालांकि, टीपीएस कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। सरदार एस्पेसी स्वीटी सहयोगी खुद केंद्र पर पहुंची और जांचना लेती नजर आईं वहीं, एएस कॉलेज परीक्षा केंद्र के पास भी एक महिला अस्थायी मोबाइल से कुछ नोट करती देखी गईं।

बांग्लादेश में 199 भारतीय सुरक्षित लौटे

नई दिल्ली। बांग्लादेश में फैली अराजकता के चलते वहां के हालात काफी खराब हैं जिसके चलते वहां रह रहे भारतीय वायस लौटने को मजबूर हैं। उन्हें वायस लाने के लिए एयर इंडिया बुकवा कर लड़खे से बाका के लिए अपनी उड़ानें चलाएगी और बांग्लादेश की राजनीति वहां से भारतीय लोगों को वायस लाने के लिए एक विशेष उड़ान भी संचालित करने की संभावना है। इसी बीच बाका से एक एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। जिसमें करीब 199 भारतीय स्टेज्ड लौटे हैं। वहीं खालिफा गैंग के बड़े तारिफ रहमान बुकवा कर बांग्लादेश लौट रहे हैं। वह शाम को बाका में एक रेली में शामिल होंगे। तारिफ रहमान कई सालों से लंदन में रह रहे हैं।

गृह मंत्रालय से रिटायर्ड बुजुर्ग की दिग्दर्शन गोली मारकर हत्या

नई दिल्ली। उत्तर नोएडा में बदमाशों के हाँसे बलुर्द हैं। यहां पार्क में टहलने आए बुजुर्ग को बदमाशों ने दिग्दर्शन गोली मारकर हत्या कर दी। वह गृह मंत्रालय से रिटायर हुए थे। दिग्दर्शन बुजुर्ग को हत्या से ग्रेटर नोएडा में दक्षत व्याप्त है। सूचना पार्क मॉक पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गया है। पुलिस के आला अंधकार भी मॉक पर पहुंच गए हैं। पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग के ऊपर तांबटोड गोली चलाकर उन्हीं हत्या कर दी। 70 वर्षीय हरि प्रसाद सुबह पार्क में टहलने आए थे। बाइक वाहन बंदना सहल पहुंचे और हॉर साइकिल को पर्सनल से गोली मार मॉक से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने बताया कि पुलिस सोसाइटी के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को सहायता से बदमाशों को पहचान करने का प्रयास कर रही है। बुजुर्ग की हत्या क्यों हुई इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि वह गृह मंत्रालय से रिटायर थे और मौजूदा समय में ग्रेटर नोएडा में रह रहे थे।

बांग्लादेश में उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास में तैनात गैरजर्नली कर्मचारियों को बुलाया जाएगा वायस

नई दिल्ली। बांग्लादेश में जारी सिपाही उठापटक के बीच भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास में तैनात गैरजर्नली कर्मचारियों को वायस लाना का फैसला किया है। फैसले को लेकर मंत्री सरकार ने एडवायजरी जारी की है। गौरतलब है कि बांग्लादेश की अप्रत्यक्ष प्रशासनिक शिखर हसीना भारत में हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं के चार और मंदिरों पर हमले जारी हैं। इसके बाद रिपॉर्ट के संदर्भित होने के बाद भारत ने पूरे घनाकम पर करीब से नजर रखी है। बाका में भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास में तैनात गैरजर्नली कर्मचारियों और उनके परिवारों की वापसी वाणिज्यिक उड़ान के द्वारा हुई है। बांग्लादेश में फर्जी आंसर शीट और पेपर मिले हैं। बांग्लादेश में दका के लिए विदेशी उड़ानें संचालित की हैं। इसके द्वारा 400 से अधिक लोगों को भारत लाया गया। अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया की विशेष उड़ान से बुधवार सुबह छह बजे सॉल्व 205 लोगों को भारत लाया गया। इंडिगो ने भी एक बयान जारी कर कहा कि ए321 नियो विमान से संचालित सॉल्व उड़ान मंगलवार रात दका से रवाना हुई थी और इसके जरिये छह बजे व 199 वयस्क सॉल्व 205 लोगों को भारत लाया गया व

नई दिल्ली। (एजेंसी)
चाहलूद मीरज यानी बाल विवाह (प्रिंसेस) एक्ट होने के बाद भी क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नाबालिग लड़कों के निकाह की इजाजत दी जा सकती है? देश को कई अदालतों इस मसले पर अलग-अलग फैसले दे चुकी हैं। नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अडिशनल सॉल्विस्ट जनरल तुषार मेहता ने इस मामले

को चौफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के सामने रखा। चौफ जस्टिस ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला दे रहे हैं और इस मामले का निपटारा भी करेंगे।
जस्टिस दी सुनवाई के लिए तारीख भी तय की जाएगी। 2022 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लड़कों को उम्र 16 साल है और लड़कियों को निकाह के पक्ष में फैसला दिया था। एनसीपीसीआर की ओर से तुषार मेहता पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट को टिप्पणी पर गेक लगाने की गुंजाइश की। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणी का असर बाल विवाह पर पड़ सकता है और पॉक्सो एक्ट पर भी असर हो सकता है। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि

कैसे कोई अनुकरण कर सकता है। जब हम मामला सुन रहे हैं। हम पूरे मुद्दे का परीक्षण करेंगे। 13 जून 2022 को पंजाब हाईकोर्ट का फैसला आया था।
कोर्ट के सामने 16 साल की लड़की और 21 साल के लड़के ने याचिका दायिल कर सुप्रीम को गृह लयाई थी। कोर्ट को बताया था कि दोनों को प्यार हुआ और 8 जून को उन्होंने शादी कर ली। याचिकाकर्ता ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर दावा किया था कि अगर लड़की पहुंचती यानी शादीक रूप से व्यवस्था होती है तो वह बालिग मानी जाती है। ऐसे में मर्ती से निकाह करने को हकदार है। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि मुस्लिम नाबालिग लड़की को धारा 195 के तहत नाबालिग लड़की प्युवटी माने जांच जाना चाहिए और उसे हाईकोर्ट ने नजरअंदाज किया। हाईकोर्ट ने इस बात को गलत व्याख्या की है कि प्युवटी और बालिग होने से निकाह वैध है, क्योंकि पॉक्सो कानून लागू है और मर्ती से भी नाबालिग के साथ संबंध अपराध है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो इस मामले में जो कानूनी खयाल उठे हैं उसका जवाब मिलेगा और आगे के लिए एक अहम नजरी बनेगा।

पहलगांम का रास्ता बंद, अब अमरनाथ यात्री बालटाल के रास्ते करेंगे दर्शन



जम्मू। (एजेंसी)
दक्षिण कश्मीर के पहलगांम के रास्ते पर लम्बत कार्य जारी है। उसे सुचारु कर काम जारी है। इसलिये इस साल की बची हुई अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री को केवल उत्तरी कश्मीर बालटाल-गुफा के रास्ते से ही गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे। 651 तीर्थयात्रियों का एक और जग्या बुधवार सुबह 5:30 बजे जम्मू शहर के भवभवी नगर से 14 वाहनों के कॉफिले में उत्तरी कश्मीर के बालटाल सिबिर के लिए रवाना हुआ। वहां देर अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी और मंगलवार तक करीब

बांग्लादेश में अराजकता ने महाराष्ट्र को बुरी तरह किया प्रभावित किया, करोड़ों का नुकसान

मुंबई। (एजेंसी)
बांग्लादेश में अशांति के कारण नासिक में प्याज निर्यात प्रभावित हुआ है। पिछले 48 घंटों से प्याज के टुक बाईर पर फसे हुए हैं। प्याज के मंगलवार आधी रात तक बांग्लादेश पहुंचने की उमीद थी। दरअसल नासिक से बांग्लादेश जाने वाले प्याज के हर दिन 80 टुक सौमा पर रोक दिए जाते हैं। अगर प्याज के टुक वहां फस गए तो वह खराब हो जाएंगे। इससे व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है और सामान्य जनजीवन असंत-व्यस्त हो गया है। जब घरे और दफ्तारों में आग लगाई जा रही हो तो बांग्लादेश जाना संकट में जाने जैसा है। केंद्र सरकार भी सुरक्षा के नजारे से कदम उठा रही है। इस वजह से बांग्लादेश जाने वाले टुक सौमा पर रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस टुक में करीब 3 हजार टन प्याज है। भारत से हर साल बांग्लादेश को प्याज का निर्यात किया जाता है। 2023-24 में भारत से कुल प्याज निर्यात का 20.3 फीसदी बांग्लादेश भेजा गया। बांग्लादेश भारत के प्रमुख आयातकों में से एक है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में चल रही अराजकता का असर प्याज के निर्यात पर पड़ रहा है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर प्याज के किराड़ों टुक फसे हुए हैं। नासिक में प्याज के 70 से अधिक प्याज के टुक बांग्लादेश के लिए रवाना होते हैं। सीमा पर प्याज के टुक रोके जाने से व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। फसे हुए प्याज को नजदीकी सीमा पर बेचे जाने की संभावना है।
- महाराष्ट्र में दंगे पर असर?
फिदलतल राज्य में प्याज की कीमते स्थिर हैं। आमत. कम होने से बाजार भाव 2000 से 2700 के बीच है। लेकिन अगर प्याज का निर्यात नहीं किया गया तो इसका असर स्थानीय बाजार पर पड़ेगा। प्याज की आमद बढ़ने से प्याज की कीमतें गिर जाएंगी, जिससे प्याज किराड़ों को भारी नुकसान होगा। इसलिये असुंभो किया जा रहा है कि केंद्र सरकार दूसरे देशों में प्याज के निर्यात पर अधिक ध्यान दे

बांग्लादेश में हिंसा के बीच शुरु हुई भारतीय एयरलाइंस की उड़ानें

नई दिल्ली। (एजेंसी)
बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है, लेकिन देश में बवाल कम होने का नशा नहीं ले रहा है। इस बीच न्याय एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें दोबारा शुरू की हैं। लेकिन अब कई भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने बड़ बलान कर बाका के लिए फिर से पलाइड सर्विस शुरू करने की तैयारी की है। सूत्रों के अनुसार, एयर इंडिया, एयर इंडिया द्वारा बाका से उड़ानें संचालित की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, एयर इंडिया द्वारा बाका से उड़ानें संचालित करने की संभावना है। ए.ए.र इंडिया ने मंगलवार को बाका लिए सुबह की उड़ान रद्द की थी, लेकिन अपनी शाम की उड़ान संचालित की थी।

नई दिल्ली। (एजेंसी)

सोम अरविंद केजरीवाल ने जेल से दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को एक पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि इस बार 15 अगस्त को दिल्ली में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी झा फहराएंगी। दरअसल दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्ट्रेडियम में कार्यक्रम आयोजित करती है। जिसमें सोम अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते हैं, लेकिन इस बार सोम केजरीवाल जेल में

अरविंद केजरीवाल ने एलजी को लिखा पत्र

है। इसलिये उन्होंने अपनी कैनिट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने की जिम्मेदारी सौंपी है। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने वीके सोमवार को सीओआई द्वारा की गई सोम केजरीवाल को गिरफ्तारी को सही उद्देश्य है।
हाईकोर्ट ने कहा था कि सीओआई के कृत्यों में उद्देश्यपूर्णता है, जिससे दिखाना है कि आप सुप्रीमो केरने उत नवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही नवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। बता

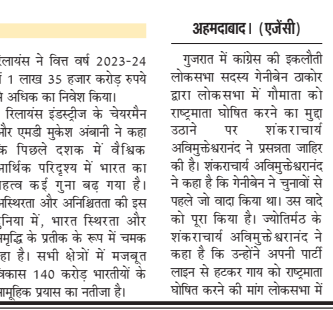
दें सीओआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था और वह इंडी द्वारा जान किए गए रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्याचिक हिरासत में है। बाद में उन्हें इंडी

हरियाणा के सालाना बजट से ज्यादा मोदी सरकार के खजाने में दिए मुकेश अंबानी ने

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1,86,440 करोड़ रुपये का योगदान दिया
में सरकारी खजाने में कुल 1,86,440 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। यह पिछले साल के मुकामले 9 हजार करोड़ रुपये अधिक है। वित्तिय साल 2023-24 में हरियाणा का बजट 183,950 करोड़ रुपये था। कंपनी ने इस दौरान सोएआर बंध में कुल 1,592 करोड़ रुपये खर्च किए और वित्त वर्ष से 300 करोड़ अधिक है। मुनाफा कंपनी में भी कंपनी जीर्ण पर रही। वित्त वर्ष 2023-24

में टैक्स के बाद लाभ 79 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। यह पिछले वित्त वर्ष से 7.3 प्रतिशत अधिक रहा। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 73 हजार 670 करोड़ रुपये रहा था।
देश की अर्थव्यवस्था में रिलायंस का योगदान काफी अहम रहा है। रिलायंस वित्तिय साल 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली देश की पहली कंपनी बनी है। वीते वित्त वर्ष की तुलना में यह 27 फीसदी

उछल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में रिलायंस दुनिया की 48वीं कंपनी है। वहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी रिलायंस ने 10 लाख करोड़ रुपये को पार कर लिया है। निर्यात में भी रिलायंस देश की मजबूत कर रहा है। पिछले वित्त वर्ष में रिलायंस ने करीब 3 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया। निर्यात ही नहीं देश में पूंजीगत परिसर्पितियों के निर्माण में भी रिलायंस निवेश क्षेत्र के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस ने वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव अंबानी ने कहा कि पिछले दशक में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अर्थव्यवस्था और अनिश्चिता की इस दुनिया में, भारत स्थिरता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में चमक रहा है। सभी क्षेत्रों में पंचवत्त विकास। 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयास का नतीजा है।



संपादकीय

पड़ोस से सबक

बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत की सतर्कता और समझदारी की सरहना करनी चाहिए। सरकार ने संसद में कोई बयान देने से पहले बांग्लादेश के विषय पर जिस तरह संवेदीय बैठक को आयोजित किया है, वह अनुकूलनीय है। विषय के लगभग सभी महत्वपूर्ण नेताओं की भी प्रशंसा करनी चाहिए कि सभी ने बैठक में भाग लिया और अपनी-अपनी बात रखी। किसी भी विवादित विषय पर कोई निष्पत्ति देने से पहले सर्वसम्मति बनाने की चेष्टा सजीव लोकतंत्र का बड़ा गुण है, जिसका अभाव बांग्लादेश में अक्सर उभरता रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश को ऐसी स्थिति में कर्तव्य नहीं करना चाहिए, जहां विधायी ढंग से कोई बयान देकर बाद में फिर फौज दखल देने को मजबूर हो जाए। बांग्लादेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी-अपनी सीमाओं का अंदाजा होता, तो यह नौकल नहीं आती। अब ऐसी नौकल आ ही गई है, तो कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम खुदखुदा न हो। बहुत अफसोस की बात है कि श्रेष्ठ हसीना के देश से पलायन के बावजूद वहां हिंसा अभी नहीं है और कथित रूप से 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह एक बड़ा संवाद है कि यहां छात्रों को अहम वया नाजिगरी है वया बांग्लादेश में छात्रों के नाम पर अस्सामियाक तत्वों ने फिर धमकाना दिया है? भारत ने ही नहीं, सूक्ष्म राइट ने भी स्पष्ट कहा है कि हिंसा तकलक रकनी चाहिए और जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। सरकार का एक व्यवस्थित ढांचा जमाने आना, तभी उपरोक्तों पर लगाम लगनी। विदेश मंत्री एक उपयुक्त न राजस्वधान में बताया है कि कई जगहों पर अलस्थितियों के व्यवहारों और मंदिरों पर हमले की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार बांग्लादेश के अलस्थितियों समुदायों की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। हालांकि, अफगानों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे अनेक तत्व होंगे, जो इस प्रकार को संप्रदायिक रूप देने चाहेंगे। जैसे, एक अफगान उड़ी थी कि वहां की फिरेक टीम के सदस्य लिटन दास के घर पर उपरोक्तों की हमला बोल दिया है। बांग्लादेश में, बांग्लादेश से आ रही खबरों को दो-तीन बार परख लेने की जरूरत है। उनके चर्चानों पर बांग्लादेशी नागरिक ही अलस्थितियों की रक्षा के लिए खड़े हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने भी बांग्लादेश में अलस्थितियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न समूहों और समुदायों की पहल का स्वागत किया है विशेष, भारत ने श्रेष्ठ हसीना को बांग्लादेश से निरस्त करने में मदद की है, पर विदेश मंत्री ने यह भी बात बतवाई है कि भारत ने श्रेष्ठ हसीना को सयान बतवरे की सलाह बार-बार दी थी और अग्रह किया था कि हालात को बातवरी से सुलझा ले। अफसोस, हसीना ने सलाह पर गौर नहीं किया और अब यूरोपीय शरण खोज रही है। यूरोपीय देश भी शरण देने से पहले विचारित है, क्योंकि उनके उनके यहां भी कहरून पेट गई है। श्रेष्ठ हसीना का पतन बतवरे में उन सभी नेताओं के लिए सबक है, जो विपक्ष या विरोधियों के लिए नहीं सोचते हैं। जो लोकतंत्र और न्याय की इज्जत नहीं करते हैं। आज के समय में सत्ता में बने रहने से ज्यादा जरूरी है- प्रतिकूल परिस्थिति न बनने देना। इसके बावजूद अगर हालात खिलाना हो जाएं, तो समय रहती सत्ता से अलग हो जाना ही इष्टतम की दिशा में है। ऐसे बदलपन से ही लोकतंत्र की ताकत बढ़ती है और अराजकता पर अंकुश रहता है।

निरंकुशता के कारण हसीना का निष्कासन

(लेखक-तलित गर्ग)

बांग्लादेश में जनभावना को दबाने एवं अनसुना करने से पहले विद्रोह, आक्रोश एवं विरोध की निष्पत्ति श्रेष्ठ हसीना सरकार का पतन। लम्बे समय से चला आ रहा आक्रोश विरोधी आंदोलन का आक्रोश उग्रतम होता गया, मगर इस आक्रोश की बुनियाद सत्ता माह पूर्व हुए चुनाव में अनियमितताओं के बाद ही पड़ गई थी। हाल के दिनों में व्यापक पैमाने पर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने श्रेष्ठ हसीना को प्रधानमंत्री पद त्यागकर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। पिछले करीब तीन सप्ताह में हुई आरक्षण विरोधी हिंसा में तीन से से अधिक लोगों की जान चली गई। दरअसल, इस संकट की मूल वजह एक लोकतांत्रिक नेतृत्व का तानाशाह एवं निरंकुश बनना बड़ा कारण रहा। जनभावनाओं को कुचला जाना एवं अनसुना करने के कारण ही हसीना आन-पानन देश छोड़कर भारत आने के लिए विवश होना पड़ा। उससे पहले पता चलता है कि हालात किस तरह बनकर खिलाने हुए थे। उसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि उनका इस्तीफा मांग रहे बंगाली प्रदर्शनकारियों ने उनके सरकारी आवास में घुसकर तो लोडफोर्ज की ही, उनके पिता एवं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले श्रेष्ठ मुजीब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के साथ उनका नाम पर बने एक संग्रहालय की भी जाना दिया। बांग्लादेशी बेहल हो गया, हिंसक एवं अराजक घटनाएं कर बने कर हसीना के खिलाफ कला बहिर्गुल बजा रही थी। जैसी आशंका थी, श्रेष्ठ हसीना के पलायन करते ही सत्ता में सत्ता संभाल ली और इमली-जुली अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की। शायद सेना द्वारा कड़ी तैयारी पहले से कर रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप के श्रीलंका, नेपाल के बाद बांग्लादेश में उग्रता होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति भारत सरकार को सतर्क एवं सावधान रहने के साथ अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है।

जब-जब जिन-जिन देशों में जनता की आवाज को दबाया गया, एक विस्फोटक स्थिति बनी, क्रांति का शंखना हुआ। मान्य सिद्धान्त है कि आदर्श ऊपर से आते हैं, क्रांति नीचे से होती है। बांग्लादेश में क्रांति एक विद्रोह का अंग नहीं बल्कि स्थिति बना कि ऊपर से आदर्श की स्थितियों पर धुलकाल छागे जा तो क्रांति नीचे से होने लगी, बांग्लादेश की जनता में बलुसमें लगा, आगजनी, लोडफोर्ज, हिंसक प्रदर्शनों में हिंसकों लोग मारे गये, सरकारी सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ। बांग्लादेश में लगातार बार बार धारणमन्त्री बनने वाली श्रेष्ठ हसीना ने जनक्रोध एवं जनता के विद्रोह को हल्के में लिया। बांग्लादेश में हसीना लगातार विस्फोटक होती स्थितियों का सावधानी से अदालत नहीं कर पायी। आरक्षण आंदोलन को दबाने के लिये की गई सख्ती ने आग में घी का काम किया। जिससे बांग्लादेश के जनमानस में गहरे तक यह भाव एवं घाव पैदा हुआ कि उनकी आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चूँकि श्रेष्ठ हसीना ने अपने लंबे शासनकाल में बांग्लादेश को स्थिरता प्रदान की और उसे आगे बढ़ाया, इसलिए उनकी सत्ता को कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ समय पहले आरक्षण के खिलाफ छात्रों की आने से शुरू हुआ आंदोलन उनके

लिए मुसीबत बन गया। इस आंदोलन को शीघ्र ही श्रेष्ठ हसीना के सभी विरोधियों और साथ ही ऐसे कुटुम्बों समूहों ने भी समर्थन दे दिया, जो पाकिस्तान की कटपट्टी माने जाते हैं। इसके चलते आरक्षण विरोधी आंदोलन सत्ता परिवर्तन के हिंसक अभियान में बदल गया। निश्चित ही पाक परस्तर राजनीतिक दलों ने इस आक्रोश को अपने लिये सत्ता का रास्ता बनाने में इस्तेमाल किया, लेकिन इस संकट को शाह देने में कई विदेशी ताकतें भी पीछे नहीं रही। श्रेष्ठ हसीना लगातार चौथी बार सत्ता में तो आई, लेकिन विपक्षी दल जनता में घांघली हुई है। इस तरह चुनावों के सौंदर्य तोर-तरकी में श्रेष्ठ हसीना की जीत को धुमिल कर दिया। जिसका अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अमेरिका नहीं गया। तभी पिछले महीनों में अपनी सरकार के लिये अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने हेतु श्रेष्ठ हसीना ने भारत व चीन की यात्रा की थी। हालांकि, इस दौरान देश में स्थिरता उसके अनुकूल नहीं थी। बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संतुलन साधने की श्रेष्ठ हसीना की नीति से चीन भी उनसे रुठ था और इसी कारण उन्हें हाल की अपनी नीति यात्रा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा था। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने प्रतिक्रान्ती ताकतों के लिये श्रेष्ठ हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। निश्चित ही श्रेष्ठ हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं था। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। बांग्लादेश में एक अरसे से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं है कि हिंसक प्रदर्शनोंकरी अभी भी हट्टुआ और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिक्रान्ती को निशाना बना रहे हैं।

हालांकि, श्रेष्ठ हसीना के खिलाफ उग्र आक्रोश के मूल में तानातिक कारण आर्थिक एवं असंगत आरक्षण ही रहा, लेकिन विश्वी राजनीतिक दल व उनके अनुभूतिक समुदाय सरकार को उखाड़ने के लिये बाकायदा मुहिम चलाये हुए थे। दरअसल, वर्ष 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी के प्रतिक्रान्ती के लिये उस सरकारी पदों वाली नौकरियों में तीस प्रशिक्षित आरक्षण का विशेष छात्रों के लिये। उनका तर्क था कि उनका कोई पद प्रशिक्षित आरक्षण का लाभ उठा चुकी है, फलतः बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस आंदोलन को हसीना सरकार दल से संभाल नहीं पायी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया था, लेकिन फिर इस संदेश को जनता में सही ढंग से नहीं पहुंचा सकी। सरकार उस नेताओं की गिरफ्तारी ने आंदोलन को उग्र बना दिया।



जानाक्रोध के चरम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आक्रामक भीड़ ने मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 'बंगबंधु' श्रेष्ठ मुजीबुर रहमान की मूर्ति फेंकने को तोड़ दिया। निरसदेह, सत्ता से विपके रहने के लिये फिर जाने वाले निरंकुश शासन की परिणति जानाक्रोध एवं जनान्दोलन के चरम के रूप में माने आता ही है।

सत्ता घटनाक्रम एवं हिंसक आंधी श्रीलंका में 2022 के विरोध प्रदर्शनों की याद ताजा कर गया, जिसमें वहां राजपक्षे बंधुओं को सत्ता से उतारकर विदेश भगाने को मजबूर होना पड़ा था। हालांकि, फिहालत बांग्लादेश से सेना ने कामान अनेक हाथ में ली है लेकिन आने वाली सरकार को उच्च बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति जैसे ज्वलंत मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। नयी व्यवस्था एवं वंचन के साथ सकारात्मक परिवर्तन हो, विदेशी ताकतों विशेषतः पाकिस्तान की कटपट्टी बनने से बचना होगा। हालांकि, भारत के हसीना सरकार से मधुर संबंध में, साथ बांग्लादेश का सबसे करीबी, सहयोगी और दुब के दिनों में भारी रहा है। श्रेष्ठ हसीना बांग्लादेश के बंग बंधु श्रेष्ठ मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 1975 में परिवार के ज्यादातर सदस्यों के साथ एक सैन्य तख्तापटन में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन श्रेष्ठ हसीना और उनकी बहन रेहाना उस जर्मनी में थी। इसलिए जिंदा बच गई थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इमली जमीन ने श्रेष्ठ हसीना और उनकी बहन को भारत बुलाया था एवं संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन हालिया उग्र-पुलक को देखते हुए हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। पाकिस्तान परस्तर बीरानी और जमात-ए-इस्लामी की अतिरिक्त पाकिस्तान के लिये सावधान होकर अस्थिरता को भी गंभीरता से ध्यान देने की है। बांग्लादेश के नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस देश के अंतरिम धारणमन्त्री बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि श्रेष्ठ हसीना का विशेष कर रहे छात्रों ने मोहम्मद युनुस के नाम का समर्थन किया है। श्रेष्ठ हसीना और युनुस का आपस में बहुत तनाव रहता है, यह युनुस से उम्मीद की जा रही है कि वह देश को स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं। भारत पड़ोसी देश के नाते बांग्लादेश में स्थिरता, शांति एवं सौहार्दपूर्ण स्थितियों को कामना करता है।

आज का राशीफल

- मेघ** - गृहीणियों वस्तुओं में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च करने से बचें। राजनिराक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे।
- वृषभ** - पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रशिक्षण में वृद्धि होगी। शासन सेवा का स्वर्णकाल होगा। शत्रुपक्ष से के लेना-देना में सार्वभौमि रहे। आरक्षण और व्यर्थ में संतुलन बनाकर रखें। बलाघ्न प्रयास में सार्वभौमि रहें।
- मिथुन** - आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संसदन के सार्वभौमि की पूर्ति होगी। भाग्यवश कुछ पैसा होगा जिसका आशंका लाभ मिलेगा। अंग प्रसंग प्रभाव होंगे। कृषि अतिरिक्त अन्य व्यवसायों से निम्नण की संभावना है।
- कर्क** - बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। पारिवारिक कठिनाई से पीड़ा मिटने के योग है। व्यवसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मनोरंजन के अतिरिक्त प्रयास प्रयास संबंध मधुर होंगे।
- सिंह** - व्यवसायिक योजना सफल होगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। पिता या उदात्तविकारी की सहायता मिलेगी। महान समर्थन एवं कला की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।
- कन्या** - रोजी रोजगार की दिशा में सफलता के योग हैं। सजावलय कार्यों में हिस्सा लेना पड़ सकता है। ध्यान-पान में संयम रखें। संसदन के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफल रहेंगे।
- तुला** - शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशांति सफलता मिलेगी। संसदन के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। अपनी का सहयोग मिलेगा। लोगों की सहायता आशंका धन लाभ करयोग। व्यर्थ की भावनाइयों को छोड़ें।
- वृश्चिक** - व्यवसायिक योजना सफल होगी। कोई भी महत्वपूर्ण निष्पत्ति न लें। आर्थिक अज्ञान होगा। संसदन के सार्वभौमि की पूर्ति होगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। बलाघ्न प्रयास में सार्वभौमि अवधि है।
- धनु** - पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यवसायिक योजना सफल होगी। धन, पद, प्रशिक्षण में वृद्धि होगी। शासन सेवा की दिशा में सुखद व लाभप्रद होगा। जीवन यात्रा का सहयोग व सार्वभौमि अवधि है।
- मकर** - बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग में आशांति सफलता मिलेगी। पिता या उदात्तविकारी का सहयोग मिलेगा। पत्र-विचार की संभावना है। अनावश्यक कार्यों का सामना करना पड़ेगा।
- कुम्भ** - स्वास्थ्य जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। धन-पान संयम रखें। आर्थिक व सार्वभौमि का सार्वभौमि प्रयास सफल होगा।
- मीन** - जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। संसदन के कार्यों निष्पत्ति रहेंगे। आर्थिक पराक्रम में वृद्धि होगी। कोई भी महत्वपूर्ण निष्पत्ति न लें। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। प्रयास प्रभाव होंगे। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा।

तो अब सरकार के निशाने पर वफक बोर्ड

(लेखक- राकेश अग्रवाल)

7 फास ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी पदकों पर अपना निशाना साध रहे हैं लेकिन हमारी सरकार के निशाने पर हमेशा की तरह मुस्लिम और उनकी संस्थाएं हैं। केंद्र के निशाने पर अब मुस्लिमों की वफक समितियों का रखरखाव करने वाला वफक बोर्ड है। सरकार वफक बोर्ड काजून में संशोधन कर बोर्ड की शक्तिया सीमित करना चाहती है। मुस्लिम है कि आप जग से आलेख पढ़ रहे हो तब वफक बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा बिल सरकार संसद में पेश कर रही हो, हालांकि केंद्रीय लेबर सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन बिल की खबर आते ही इंगामा शुरू हो गई है। एसाइडमआइडम से लेकर कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। सांसद अरसुददीन ओवेयी ने कहा कि यह संशोधन में दिग् धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है।

आजको पहले ये जानना होगा कि आखिर वफक बोर्ड के क्या हैं? केंद्रीय वफक परिषद वफक बोर्ड के कामकाज से सम्बन्धित मुद्दों और देश में वफक के सम्बन्धित प्रशासन से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में प्रशासनिक दृष्टि से के लिए केंद्रीय वफक परिषद की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गई। इस बोर्ड की स्थापना भाजपा के जन्म से सोलह साल पहले तत्कालीन केंद्र सरकार ने दिसम्बर, 1964 में वफक अधिनियम 1995 के अन्तर्गत की थी। वफक के प्रभारी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय वफक परिषद के 20 अय सदस्य होते हैं केंद्रीय वफक परिषद इन समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसके द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएं हैं। वफक अरवी भाषा के वफक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दहरना। इसी से बना वफक

वफक एक ऐसी संपत्ति होती है, जो जन-कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वफक दान का ही एक तरीका है। इस्लाम की तरह हम समानताओं में धार्मिक स्वतंत्रता है। हमारे सब जिनमें भी धार्मिक स्वतंत्रता है, उनके स्वतंत्रता के लिए तत्कालीन शासकों, राजा-महाराजाओं, नवाबों और निजी व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग दान की जाती रही है। उनके रखरखाव के लिए भी वफक बोर्ड जैसी ही वफक वस्थाएं हैं, लेकिन निशाने पर वफक है क्योंकि वो अल्पसंख्यक मुसलमानों का है, और मुसलमानों से हमारी सरकार को है। सरकार ने 2024 के आमचुनावों में खुदकर मुसलमानों का नाम तकर बहसस्थल हिन्दू मतदाताओं को आतंकित करने की कोशिश की थी। कहा था कि जनता का मंगलसूत्र खतरों में पड़ जाएगा।

बहरहाल मुस्लिम नेताओं की वफक है कि मोदी सरकार वफक बोर्ड की खयालत को छिपाना चांती है। भाजपा शुरू से ही वफक और वफक परिषदों के खिलाफ है। वह अपने हिंदुत्व एकांते के तहत वफक संपत्तियों और वफक बोर्ड को खत्म करना चाहती है। अगर हममें कोई संशोधन किया गया तो प्रशासनिक अराजकता बढ़े होगी और वफक बोर्ड अपनी स्वयत्पत्ता खो देगा, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। हमारी सूचना है कि प्रस्तावित वफक में वफक बोर्ड संपत्तियों पर किए गए सभी दावों को अनिवार्य स्थापना से गुजरना होगा। वफक बोर्ड के अधिकारों, उसकी ताकतों और उसकी कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया जाएगा। महिला सदस्य राज्यों में वफक बोर्ड का हिस्सा होंगे। प्रस्तावित बिल में अजून तक कानून से जुड़े कई वतांज हटाए जा सकते हैं। उनके मुताबिक वफक बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संपत्तियों को हटा दिया जा सकता है।

सरकार संवैधानिकता होती है, वो वफक कुछ कर

सकती है, लेकिन इस सब कुछ कि पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। सवाल यह है कि वफक बोर्ड ऊपर सरकार की वक दुष्टि है क्यों? इकाई सीधा सा जवाब है वफक के पास अलग संपत्ति का होना। एक सूचना कि मुताबिक वफक बोर्ड अनेक के मामले में रूसी और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे नंबर पर है। आकांक्षी के मुताबिक वफक बोर्ड के पास 8 लाख एकरड से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में एक जमीन 4 लाख एकरड आ करती थी, जो कुछ सालों में बढ़कर दोगुनी हो गई है। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा, और कंगराह हैं। पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि दिसंबर 2022 तक वफक बोर्ड के पास एक करोड़ 86,65,644 अक्षर संपत्तियां थीं, जाहिर है की वो सामाजिक मुस्लिमों द्वारा वफक की गयी है, यानि व सरकारी नहीं है, लेकिन सरकार को ये संपत्तियां चाहिए।

हाकीकत यह है कि वफक की संपत्तियों का दुरुूपयोग ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे हिन्दू मंदिरों की संपत्तियों या ईसाई मिशनरियों की संपत्तियों का है। इन सभी का निम्नण जरूरी है क्योंकि अतिथी मंदिरों और वफक की संपत्तियों को असरदार लोगो ने या तो खुद-ब-खुद कर दिया है या फिर उनके ऊपर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। आरोप है की अकेले ओबेसी के पास वफक की 3000 करोड की वफक संपत्तियां हैं। देश कि अनेक राज्यों में वफक की संपत्तियों को लोकर अदालतों में मुकदमों चला रहे हैं। मुझे पता है कि कानून कि होते हुए भी न वफक की संपत्तियां महफज है और न दूसरे धर्मों की साम्पत्तियां। जैसे मुझा-मौलवियों ने वफक संपत्तियों को खुद-ब-खुद कर दिया है वैसे ही मदी की संत-महत्तो ने मंदिरों की संपत्तियों को या तो बेच खयाया है या मामूली से किराये पर अरसरदार लोगो

को दे दिया है। लेकिन सरकार को वफक संपत्तियों की ज्यादा फिक्र है। दूसरे मजबूतों की संपत्तियों की नहीं। दरअसल वफक एक तीर से दो निशाने साध रही है। एक तरफ सरकारी वफक संपत्तियों पर अपना अधिपत्य बढ़ाना चाहती है और दूसरी ओर अल्पसंख्यक मुस्लिमों को सबक भी सिखाना चाहती है क्योंकि आम चुनाव में अल्पसंख्यकों ने सरकारी पार्टी को बुरी तरह से खारिज कर दिया। यदि जैडई और टीडीपी भाजपा का साथ न देती तो भाजपा को आज विपक्ष में बैठना पड़ता। भाजपा ने पिछले दस साल में मुस्लिमों कि कल्याण कि नाम पर उनका जितना नुकसान किया है उतना पहले किसी ने भी नहीं किया। केंद्र में भाजपा की सरकार के रहते अयोध्या में नया राममंदिर बन गया लेकिन नयी मस्जिद नहीं बनी। वयोकि सरकार को मस्जिद बनाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। सरकार का काम भी नहीं है मस्जिद बनाना। सरकार तो मुस्लिमों की है ही नहीं। मध्यप्रदेश में तो सरकार एक कदम आगे जानकर पहली बार कुमजामन अरबी संपत्तियों को भी संपत्तियों का है ही नहीं। मध्यप्रदेश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में मोहन वदय मूकधरजी ने हार जी। हम या आप सरकार को उसका काम करने से नहीं रोक सकते हैं। ये काम विपक्ष का है। हमारा पक्ष तो केवल आवाज करने का है। हमारा पक्षे भी कठना था और आज भी कठना है कि सरकार को सभ्यता सत्ता लेकर सबका विकास करना चाहिए। यदि सरकार हिन्दू-मुसलमान कि फर में पड़ी रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह नफरत की आग में झूसलते नजर आये। इतने समय रहते वफक वफक किये जाते तो बहुत, अन्यथा होगा वो ही जो भाजपा और सारे जी व सर कर रहा है। राम जी का इस्में कोई रोल नहीं है।

विचारमंचन

(लेखक- सन्त जैन)

पिछले 10 वर्षों से आम जनता के ऊपर लगातार टैक्स और शुल्क बढ़ाए जा रहे हैं। आम जनता की ओर से चुने गए सांसद और विधायकों के वेतन भत्तों को पसा खदे कर रहे हैं। आम जनता की ओर से चुने गए सांसद और विधायकों के वेतन भत्तों को पसा खदे कर रहे हैं। वहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन बढ़ाई जा रही है। सांसद, विधायक और मंत्रियों को क्रीमी लेयर की श्रेणी का सम्मान और धन प्राप्त हो रहा है। उरसे अनेक जनों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। आम जनता टैक्स की मार से फण्ड रही है। जब देश स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद राजनीति में सद्गुण परिवारों के बुजुर्ग आने बरवों को राजनीति में नहीं भेजना चाहते थे। उनका मानना था, जन्मजात के लिए घर का पसा खदे कर रहे। घर के कामकाज और व्यापार में कोई लचि नहीं लेते। बहुत मुश्किल से लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते थे। उस समय विधायक और सांसद

आम जनता पर टैक्स की मार, सेवकों पर सरकार मेहरबान

को इतना पैसा भी नहीं मिलता था। वह सब के समय राजधानी जाकर अपना खर्च पूरा कर सके। पिछले तीन दशक में स्थितियां बड़ी तेजी के साथ बदरी हैं। विधायकों और सांसदों के वेतन भत्ते लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। सांसद और विधायकों की अल्पसख्यकियों भी बढ़ रही हैं। रतवे और हवाई जहाज में मुफ्त यात्राएं करने का मौका मिल रहा है। बिजली पानी की भी मिल रहा है। रहने के लिए आवास फल मिलता है। कई राश्यों में तो मंत्रियों और विधायकों को आसकर भी सरकार द्वारा भरा जा रहा था। कार्यकाल खत्म होने के बाद पेंशन मिलती है। जितनी बार के विधायक-सांसद उसी के अनुसार बड़ी हुई पेंशन आजीवन मिलती है। एक बार चुनाव जीत गए, तो सारे जीवन नित्यक यात्रा करने की पत्रता हो जाती है। यह सार खर्च आम जनता द्वारा दिए गए टैक्स से सरकार करती है। जो जनता इन्हे ठोके देकर चुनाव जीतती है। उसके बाद जीवन भर उसका बोझ भी उठती है। पिछले वर्षों में राजनीति की व्यापार

बन गया है। विधायक, सांसद और मंत्रियों के परिवारजन बड़े-बड़े ठेके लेते हैं। उन्हें ही ठेके मिलते हैं। चुनाव जीतने के पहले जितनी हेसियत चुनाव खर्च देनी की होती है। कुछ वर्षों में बड़े करों-अवकों रुपरे के मालिक वर और उन्हे परिवार के लोग बन जाते हैं। एक वफक पर लगातार टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। 8 वर्ष पहले जीएसटी कानून लागू किया गया था। इस कानून को लागू करने का उद्देश्य था कि अराजकता को खत्म करके ऐसी टैक्स व्यवस्था लागू करनी जाए। सांसद और सभी राज्यों में एक समान हो। नामांकों को टैक्स से राहत देने का भरोसा जताया गया था। जीएसटी लागू होने के बाद बहुत सारे व्यवसाय और अल्पसख्यक टैक्स बढ़ किए जाने थे। जो केंद्र एवं राज्य सरकारों ने अनाक तब नहीं किया। उरते सेन और सरपाला लोकर आम जनता से जाज्या कर की तरह टैक्स बढ़ाए जा रहा है। पेट्रोल डीजल और आयतित सामान सससे बड़ा उदरगार है। आम जनता पर टैक्स की दरो को बढ़ाकर

8, 12, 18 और 28 फीसदी कर दिया। 2016 के तूलना में वह इतल हो गया है। गरीब जनता से भी जीएसटी में भारी टैक्स वसूल किया जाना है। जीएसटी कर के दारे में सेवाओं की भी शामिल किया गया। रतवे की टिकट हो, बिजली का बिल, नगर निमाण का टैक्स, कॉलेज की फीस, बैंक के शुल्क और सरसर्वन इत्यादि का पैसा कोई संकेत नहीं छोड़ेगा। जो जीएसटी में कवर न होता हो। जीएसटी लागू होने के पहले जीएसटी के रूप में केंद्र सरकार को मार बार फीसदी का टैक्स मिलता था। जब से जीएसटी लागू हुआ है। उसके बाद से केंद्र सरकार की कमाई कई गुना बढ़ गई है। वहीं राज्य सरकारों की कमाई जीएसटी लागू होने के बाद घटती चली जा रही है। राज्य सरकारों के ऊपर आश्रित होती जा रही है। रही सही करर टैक्स राज्य सरकारों का सस, कई गुना लाइसेंस फीस बढ़ाने और जुर्माने के रूप में टैक्स की वसूली बडे पैमाने पर की जा रही है। पिछले एक दशक में आम

जनता से भारी टैक्स वसूल जा रहा है। जनता टैक्स के बोझ से कराह रही है। आम जनता ने जिन लोगों को वोट देकर चुनाव जीतवा। विधायक और सांसद बनाया। वह मोंस कर रहे हैं। उनके वेतन भत्तों को पसा खदे कर रहे हैं। गरीबों की ओर से कोई सुवाचन नहीं हो रही है। आम जनता वे वक का पीछे बंधन नहीं भी खा पा रही है। यह पिछले 10 सालों के टैक्स का सस है।

सामान्य व्यक्ति पर टैक्स को कोई सीमा नहीं है। आम जनता से कई तरह से टैक्स वसूल किया जा रहा है। जिन परिवारों की आय 5 लाख रुपए वार्षिक से कम है। उन्हें अपनी आय का 60 से 65 फीसदी तक विभिन्न टैक्स चुकाना पड़ेगा। आम जनता को 35-40 फीसदी आय को ही वह अपने परिवार में खर्च कर रहे हैं। जिस कारण गरीबों और मध्यम वर्ग के बीच में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। सरकार को लगना है, गरीबों और मध्यम वर्ग की परिवारों के पास बहुत पैसा है।



दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भारतीय संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए है। इसका वैभव, बेहतरीन शिल्प और परम आनंद का अनुभव इस मंदिर की ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर का दर्शन हमें भारत की श्रेष्ठ और प्रसिद्ध कला की याद दिलाता है। अक्षरधाम मंदिर पर्यटकों को भारत की प्रसिद्ध कला की यात्रा पर ले जाता है। इसे स्वामीनारायण अक्षरधाम के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मूल्यों और मानव सभ्यता के विकास में भागीदारी का जीता जागता उदाहरण है- अक्षरधाम मंदिर।



अपने शिल्प सौंदर्य से मन मोह लेता है

कुछ बरस पहले इस मंदिर को निर्माण शुरू हुआ तो यह सभी के लिए कोहल का विषय था। धीरे-धीरे इसका निर्माण होता गया और एक दिन अपने शिल्प सौंदर्य से सभी को मोहित कर लिया। प्रमुख स्वामी महाराज जी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण सस्था, ग्यारह हजार स्वामीनारायण भगवान को समाहित यह पारंपरिक मंदिर भारतीय ऐतिहासिक कला, संस्कृति और वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है।

निकट बरनी अभिषेक

इस मंदिर में यह प्राथम्य पारंपरिक ढंग से दुनिया की शांति के लिए की जाती है। 151 पवित्र नदियों का पानी, झील और तालाब के पानी से

अपने, परिवार और दोस्तों के लिए प्रार्थना की जाती है। मंदिर में मौजूद तीन हाल में अलग-अलग जीवन के मूल्यों को सिखाया जाता है। हाल-एक में मानव मूल्यों को फिल्म और रोबोट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इनमें अहिंसा, ईमानदारी, पारिवारिक सामंजस्य और आध्यात्मिकता का प्रतिरूप दिखाया जाता है।

हाल नंबर दो में ग्यारह साल के योगी नीलकण्ठ द्वारा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की अविश्वसनीय कहानियां सुनने को मिलती हैं। यहां भारतीय वास्तुकला और कला का बेहतरीन और कभी न भूलने वाला अनुभव होता है। यह हमारे त्योहारों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करता है। उन्हें समझने में मदद करता है।

हाल-तीन के कल्चरल बोट राइड में भारत के दस हजार साल की

अक्षरधाम

विरासतको खूबसूरती से दर्शाया गया है। भारत के ऋषि वैदिकानों के अविचार और प्रयोग के बारे में जानने को मिलता है। शाम के समय यहां आप संगीतयुक्त फव्वारों का पदम भिन्दत का आनंद ले सकते हैं। यहां जन्म, जीवन और मृत्यु को दार्शनिक तरीके से चित्रित किया गया है। 160 एकड़ में फैला यहां का बगीचा मैदान और तांबे की मूर्तियां दर्शनीय हैं।

यहां का लोटस गार्डन भी ध्यान आकर्षित करता है। अक्षरधाम मंदिर कलाकृति और खूबसूरती का बेमिसाल उदाहरण है। यहां अर्ध सुबह 9.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक जा सकते हैं। यहां किसी भी मौसम में जाया जा सकता है। सोमवार को यह मंदिर बंद होता है। मोबाइल फोन ले जाना और फोटो खींचना यहां मना है।

कन्याकुमारी, जहाँ मिलते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी



भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित पवित्र स्थान कन्याकुमारी के बारे में कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जब ज्ञान की खोज में निकले थे तो यहीं पहुंच कर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में आकर मिलते हैं। इसलिए यहां तीन अलग-अलग रंगों की रेत देखने को मिलती है। शहर की भीड़ से दूर तथा तनाव व शोरगुल से भी दूर यह स्थान बड़ा शांतिमय है। यहां यदि शोर है तो वह है सिर्फ समुद्री लहरों का, जो कि कानों में संगीत की तरह गुंजाता है। कन्याकुमारी के सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य तो देखते ही बनते हैं।

कन्याकुमारी का मंदिर कन्याकुमारी को ही अर्पित है। इस मंदिर को भारत के छोरों का रखवाला भी माना जाता है। इस मंदिर को मद्दुरै, रामेश्वर और तिरुपति आदि मंदिरों की तरह ही पवित्र माना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां केवल हिन्दू ही जा सकते हैं। यह मंदिर प्रातः चार बजे से लेकर ग्यारह बजे तक तथा उसके बाद सायं 3.30 से लेकर 8.30 तक खुला रहता है। यहां विवेकानंद जी का स्मारक भी है। यह समुद्र के बीच एक विशाल शिला पर स्थित है। इस शिला पर बैठ कर ही स्वामी विवेकानंद जी ने साधना की थी। स्मारक के कक्ष में विवेकानंद जी की विशाल मूर्ति भी है। स्मारक स्थल से चारों ओर फैले विशाल समुद्र का दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। कन्याकुमारी में महात्मा गांधी का स्मारक भी है। यहीं पर महात्मा गांधी का अस्थि कलश रखा गया था। यह स्मारक कन्याकुमारी मंदिर के ठीक पास ही बना हुआ है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र यह स्मारक अपनी अद्वैत कलाकृति के

लिए भी जाना जाता है। कन्याकुमारी से लगभग 34 किलोमीटर दूर स्थित उदयगिरि किला भी देखने योग्य है। इस किले की 18वीं शताब्दी में राजा मारुत वर्मा ने बनवाया था। इसके साथ ही आप गुगनन स्वामी मंदिर भी देखने जा सकते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह करीब एक हजार साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में

एक चोल राजा ने बनवाया था। कन्याकुमारी आए हैं तो सुविधम देखना नहीं भूलें। यह कन्याकुमारी से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है। 9वीं शताब्दी के शिलालेख इस मंदिर में पाए जाते हैं। यहां पर भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है। यहां पर हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति है जो कि यहां की मूर्तिकला का जीता-जागता उदाहरण है। नागरकोयिल नागराज का अद्भुत मंदिर है। नागराज का मंदिर होते हुए भी इसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। यहां का द्वार चीनी शिल्पकला में बनाया गया है। यहां आपको देखने को मिलेगा कि भक्तों को दिया गया प्रसाद जमीन से निकाला जाता है। यहां नागलिंग फूल भी पाया जाता है। यह मंदिर कन्याकुमारी से बीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको आसानी से बसें मिल जाएगी और यदि आप चाहें तो बंगलौर, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, मद्दुरै आदि जगहों से यहां रेल व सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं।

शानदार धरोहर है हुमायूँ का मकबरा

भारत में मुगल शासन की नींव रखने वाले हुमायूँ को लोग आज भी उनकी राजशाही टाटबाट से नहीं बल्कि हुमायूँ के मकबरे से ज्यादा याद करते हैं। दिल्ली स्थित यह मकबरा मुगल धरोहरों में सबसे शानदार धरोहर है। यह मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण है। इस मकबरे के बनने के कई शताब्दी बाद इसी तर्ज पर ताजमहल का निर्माण हुआ। इस मकबरे का निर्माण हुमायूँ की पत्नी हमीदा बानु बेगम ने अपने पति की मौत के नौ साल बाद शुरू करवाया। यह फारसी वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है। इसके आगे बने बगीचे को चहारबाग कहते हैं। यह बगीचा चार मुख्य भागों में विभाजित है जहां से लोगों का आना जाना होता है। इन रास्तों को खूबसूरत बनाने के लिए बहते पानी का रास्ता बनाया गया है। 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच कई मुगल शासकों को इसी मकबरे में दफनाया गया था। हुमायूँ के इस मकबरे को नेक्रोपोलीस (मृत शरीरों से प्रेम) नाम भी दिया गया है। भारत के किसी भी शहर में मुगल शासकों और उनके रिश्तेदारों के इतनी कब्र कहीं देखने को नहीं मिलती। भारतीय उपमहाद्वीप में यह पहला ऐसा मकबरा है। हुमायूँ के मकबरे का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। दो मंजिला यह मकबरा सफेद मार्बल के गुंबद से ढका हुआ है, जो देखने में आकर्षक है। इस मकबरे की ऊंचाई 47 मीटर और चौड़ाई 9.1 मीटर है। वहां के गलियारे, खिड़कियों में भी फारसी वास्तुकला झलकती है। कुछ जगहों पर भारतीय शैली की भी झलक देखी जा सकती है। कुल मिलाकर यहां 150 कब्र हैं जो चारों तरफ से गार्डन से घिरी हैं। इस मकबरे के बनने के बाद ही इसका पतन शुरू हो गया था। मुगल बादशाहत जैसे-जैसे खत्म हुई उनके बनाए स्मारकों का भी पतन होना शुरू हो गया। मकबरे की आसपास बने बगीचे में लोगों ने सड़कियां उगानी शुरू कर दीं। 1857 में ब्रिटिश ने इंग्लिश स्ट्राइव गार्डन बनाया। 1903-1909 के बीच इस बगीचे को अपनी खोबी हुई असली

खूबसूरती लार्ड कर्जन से मिली। अभी कुछ साल पहले मकबरे का पुनरुद्धार होने के बाद से इसकी चमक अब देखने लायक है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर माना है। इस मकबरे की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए इस पर काफी काम किया गया है। इसकी शां-ओ-शौकत अब देखने लायक है। हुमायूँ के मकबरे को देखने कभी भी जाया जा सकता है। दिल्ली आने पर टैक्सी या आटो से यहां आप पहुंच सकते हैं। बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है। परिसर के बाहर पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। जलपान और शौचालय के लिए भी भटकना नहीं पड़ता। परिसर के एक किनारे इसका भी इंतजाम है।



दवा कंपनी का नेट प्रॉफिट 77 प्रतिशत बढ़ा.....शेयर 6 प्रतिशत उछला

मुंबई। भारतीय फार्मा कंपनी लुपिन का शेयर 6.18 प्रतिशत तक उछल गया। इसके साथ ही लुपिन का स्टॉक वॉल्यूम पर 52 साप्ताहिक उच्च लेवल 2025 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। बता दें कि कंपनी के शेयरों में यह तेजी पहली तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद आई है। दवा बनाने वाली कंपनी लुपिन का चारू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट 77 प्रतिशत बढ़कर 801 करोड़ रुपये हो गया। मुंबई स्थित कंपनी ने गत वित्त वर्ष 2023-24 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में 452 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कायदा था। अलग-अलग बाजारों में मजबूत बिक्री के चलते कंपनी का मुद्राभाज बढ़ा है। लुपिन ने कहा, पहली तिमाही में ऑपरेशन से कमाई बढ़कर 5,600 करोड़ रुपये हो गई जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह 4,814 करोड़ रुपये थी। लुपिन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीलेश गुप्ता ने बताया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में जो जोति बनाई, उसका फल यह तिमाही मजबूत रही। नए उत्पादों, प्रमुख क्षेत्रों और हमारे परिवारवादी मुद्रांक और प्रॉफिटैबिलिटी में सुधार से हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा। लुपिन की अप्रैल-जून तिमाही में भारत में 1926 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में 1,638 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी।



पलाइंट टिकट पर पाए 18 प्रतिशत तक की छूट

नई दिल्ली। यात्रियों को हर पलाइंट बुकिंग पर बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है। 8 अगस्त तक यात्री अपनी फ्लाइट की रीब्रेन्डिंग के लिए पलाइंट बुकिंग पर 18 प्रतिशत तक की छूट पा सकते हैं। इंडीगो ने अपने 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर करमसर के लिए स्पेशल सेट की घोषणा की है। इस सेट के तहत, पैसंजर्स को पलाइंट बुकिंग पर 18 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा, यह छूट केवल इंडीगो की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग करने पर उपलब्ध होगी। इंडीगो ने अपने करमसर के लिए हेमिंग्गो इंडीगो डे सेट की घोषणा की है, जो 5 अगस्त से 8 अगस्त तक चलेंगी। इंडीगो के नए ऑफर में पैसंजर्स को पलाइंट टिकट पर 18 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए पैसंजर्स को इंडीगो की वेबसाइट से बुकिंग करनी होगी और स्पेशल कोड का उपयोग करना होगा।

कच्चे तेल की कीमतों में आसक्तता है गिरावट

न्यूयार्क। कच्चे तेल के दाम अपने वाले समय में गिर सकते हैं। एक सप्ताह के भीतर में कच्चा तेल 2025 में मंदी आने के कारण कच्चे तेल (ब्रेट क्रूड) की कीमतें 75 डॉलर प्रति बैरल से 90 डॉलर प्रति बैरल के बीच रह सकती हैं। इस प्रतिक्रिया में कच्चा तेल है कि अगर आर्थिक मंदी आई तो नाभयिकरण पर कच्चे तेल के दाम गिरकर 30 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकते हैं। वहीं, ब्रेट क्रूड के दाम 50 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकते हैं। अभी 7 अगस्त 2024 को नाभयिकरण पर क्रूड का भाव 73 डॉलर प्रति बैरल है जबकि ब्रेट क्रूड का दाम 76 डॉलर प्रति बैरल है। कच्चा तेल सस्ता होने भारत के लिए लाभप्रद रहेगा। ऐसे में भारत का खर्च कम होगा। इससे चावल वित्तीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ समय में पेट्रोल-डिजल की कीमत (Petrol-Diesel Price) का खराब प्रदर्शन नहीं किया। इससे सरकार को दो बड़े लाभ होंगे हैं। इससे देश के चालू खाता घाटा कम हुआ है। इसके अलावा सरकार के राजस्व में वृद्धि आई है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से हाल में एक और अच्छी खबर आई है। सुरंग शब्दों में कच्चे तेल के प्रमुख निर्यातक मुद्रा में 4.99 फीसदी मजबूती आई है। इससे सरकार को विदेशों से सामान खरीदने में कम भुगतान करना पड़ेगा। रूपए के मजबूत होने से कच्चा तेल, इलेक्ट्रिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स सेक्टर को सीधा फायदा होगा है। इससे आयात की लागत घट जाती है। हालांकि, इससे कुछ सेक्टरों को नुकसान भी होना है। फूड की कीमतों में गिरावट से तेल कंपनियों को लाभ होगा।



जुकुर्बर्ग ने लगाई अमीरों की सूची में छलांग, एक दिन में कमाए 70 हजार करोड़

नई दिल्ली। एक शास्त्र एक ही रात में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया वह अमीरों की सूची में तीसरे नंबर पर है। जी हां, यह शास्त्र फेंसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क जुकरबर्ग फेंसबुक की फॉन्डिंग राउंड के सीईओ हैं। जुकरबर्ग की संपत्ति एक दिन में दस से बीस हजार करोड़ नई कमाई 70 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा बढ़ गई है। इसकी बढोतरी होने वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में तीसरे

मोदी सरकार से आया प्रस्ताव.....गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर बना सैकेट

मुंबई। रिटायर्डी शेयरों में बुधवार को इंटू-टू ट्रेड के दौरान तेजी देखी गई, गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर 4 फीसदी तक चढ़ गया। बता दें कि रिटायर्डी स्टॉक्स में तेजी मोदी सरकार की ओर से रिफ्ल एस्टेट संपत्तियों पर कैपिटल गेन टैक्स के मामले में टैक्स प्रत्यक्ष को राहत देने के प्रस्ताव के बाद आई है। प्रस्ताव के अनुसार, अब संपत्ति मालिकों के पास कैपिटल गेन टैक्स पर 20 प्रतिशत या 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा।



संशोधित प्रस्ताव के मुताबिक, 23 जुलाई 2024 से पहले मकान खरीदने वाला कोई व्यक्ति या हिंदु अविवाहित परिवार (एचयूएफ) महाराष्ट्र के प्रभाव को शामिल किए बिना 12.5 प्रतिशत को नई योजना के तहत टैक्स देने का विकल्प चुन सकता है। इसके अलावा उनमें पास पुरानी योजना के तहत इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत

रुपया सपाट बंद

मुंबई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया एक पैसे की गिरावट के साथ ही 83.96 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार सुबह रुपया 83.95 पर खुला। वहीं गत दिवस रुपया 83.92 पर बंद हुआ था। इस प्रकार उम्मी नगरी आई है। गत दिवस वैश्विक बाजारों और घरेलू शेयर बाजारों में तेजी से रुपया सुर्ख-आती कारोबार में अपने सर्वकालिक निचले स्तर से 25 पैसे की बढ़त के साथ 83.84 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। जानकारों का कहना है कि घरेलू बाजार में उछलते स्थानीय मुद्रा को थोड़ा समर्थन मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति, पंडित एशिया में पू-राजनीतिक तनाव में युद्ध और विदेशी पूंजी की निष्कर्षा ने निवेशकों को तणाव को प्रभावित किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रिक विदेशी मुद्रा वित्तीय बाजार में रुपया 83.92 प्रति डॉलर पर खुला। सुर्ख-आती सौदे के बाद 83.84 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 25 पैसे की बढ़त को दिखाता है। रुपया सीमावर्ती को अपने सर्वकालिक निचले स्तर 84.09 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। दिन भर के कारोबार के बाद छह मुद्रा मुद्राओं में मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को अंकने वाला डॉलर सूचकांक 0.16 फीसदी की गिरावट के साथ 102.85 पर रहा।

मूटान में दिखेगा टाटा समूह का दम.....पॉवर प्रोजेक्ट में होगी हिस्सेदारी

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप अब मूटान में अपना दम दिखाने को तैयार है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर अपने ग्रीन एनर्जी पोटेंशियल को बढ़ा रही है। इस योजना के तहत कंपनी मूटान में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 830 करोड़ रुपये में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी। 600 मेगावाट की क्षमता वाले प्रोजेक्ट के लिए 6900 करोड़ रुपये की निवेश की जरूरत होगी। इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी खरीदने के बाद खरोलीयू हाइड्रो पावर टाटा पावर की सहायगी कंपनी बन जाएगी। टाटा पावर 600 मेगावाट का स्टेशन डेवलपमेंट के लिए एक ग्रीन पावर के साथ पार्टनरशिप करेगी। इस मौके पर कंपनी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट टाटा पावर को अपने वित्तीय और ग्रीन एनर्जी ट्रान्जिशन को तेज करने में मदद करेगा। टाटा पावर ने कहा कि यह लवजमर्ग स्टॉक एक्सचेंज से अपने गैर-पब्लिक लिमिटेड कंपनी (जीडीएल) को समाप्त करेगी। इसका कारण बताकर कंपनी ने कहा कि इसमें पिछले कई वर्षों से कोई गतिविधि नहीं हुई है। टाटा पावर ने एक रगुलेटिंग फाइलिंग में कहा कि जीडीएल में पिछले कई वर्षों से कोई गतिविधि नहीं हुई है। कंपनी ने कहा कि वह जीडीएल प्रोग्राम को खत्म करने के लिए जरूरत करद उपयुगी और इस लवजमर्ग स्टॉक एक्सचेंज से हटाया जाएगा। टाटा पावर ने 4 फीसदी बढ़कर 1189 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं इस अवधि के दौरान कंपनी के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी आई है। यह 12 फीसदी बढ़कर 16810 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह रेवेन्यू 15213 करोड़ रुपये था।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 874 अंक , निपटी 304 अंक ऊपर आया

मुंबई। घरेलू शेयर बाजार बुधवार को बढ़त पर बंद हुआ। इसी के साथ ही पिछले दो दिनों के जारी गिरावट रुक गयी। आज सुबह दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी से बाजार की बढ़त के साथ सुर्ख-आती हुई और पूरे दिन यही सिलसिला जारी रहा। कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 874 अंक की बढ़त लेकर 79,468 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निपटी में भी 304 अंक की तेजी रही और ये 24,279 पर जाकर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़ रही। इसी कारण आईटी इंडेक्स 2 फीसदी उछला। एनबीएफएमआई और सरकारी शेयर भी बढ़त पर बंद हुए। ब्याजदर में जारी हिंसा के कारण अंतर्राष्ट्रिक कपाड़ उद्योग में कामकाज बंद है। ऐसे में भारतीय कपाड़ उद्योग को और विदेश खरीदारों का रुख हो सकता है। जिससे भारतीय कपाड़ कंपनियों के शेयर में भारीतर उछल आया है। आज कारोबार के दौरान एनएसई 2.23 फीसदी, इन्फोसिस 2.19 फीसदी, एचएसडी टेक्नोलॉजी 2 फीसदी ऊपर आया जबकि



अबुजी पॉट का शेयर 1.55 फीसदी और जूहुलू क्लडरदथ में भी 1.50 फीसदी की तेजी आई। वहीं मिडकैप कंपनियों में शामिल ऑनल डेविया के शेयर 6.89फीसदी, लुपिन के शेयर 4.30 फीसदी उछले जबकि स्मॉलकैप कंपनियों के शेयरों की बारा करे तो पुपती शेयर 10.25शेयर , एस्पीकल 8.96 फीसदी और आईएफपी डेविया के शेयर 7.57 फीसदी बढ़े। वहीं गत दिवस बाजार नीचे आया था। इससे पहले आज सुबह सुर्ख-आती कारोबार को बढ़त के साथ खुला। सुभाह के तीसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये बढ़त दुनिया भर से मिले सकारात्मक संकेतों के साथ ही खरीददारी से आई है। सुर्ख-आती कारोबार में बाजार ने सकारात्मक सुर्ख-आती 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 963 अंक ऊपर आकर 79,556 पर पहुंचा जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निपटी 294 अंक बढ़कर 24,286 के स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान मिडकैप इंडेक्स 1.37 फीसदी और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.01 फीसदी ऊपर आया। निपटी में ओएनपीसी, कोरॉ इंडिया, शीरो मोटोकॉर्प और एनएसई के शेयरों में बढ़त रही

मॉनेटरी पालिसी कमिटी आज करेगी ब्याज दरों को लेकर ऐलान

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पालिसी कमिटी (एपीसी) 8 अगस्त को ब्याज दरों को लेकर अपने फैसले का ऐलान करेगी। सर्व के अनुसार, भारतीय रुपया का आउटकूप पिछले महीने से वृद्धिबद्ध बढ़ा है। ऐसा इतिहासिक क्योंकि आरबीआई ने इंडियन करेंसी को एक स्थितिदार दरों से रखने का प्रयास किया है। बता दें कि आरबीआई (आरबीआई) ने मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच रेपो रेट में 2.5 प्रतिशत बढ़कर 6.5 फीसदी कर दिया था। इसके बाद से एपीसी ने पिछली आठ मॉनेटरी पालिसी में ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। इस बारे में आर्थिक

जानकार ने कहा, 'फूड इन्फ्लेशन जोखिम को लेकर पालिसी का रुख सतर्क होगा। गतिविधि के दौरान लू चलने और जुन में मॉनसून की सुलु चल जैसे प्रतिकूल मुद्दों के कारण खाद्य महंगाई के बढ़ने का दवाव बना हुआ है। रोजाना खाने-पीने की चीजों की कीमतों में संकेत मिलता है कि जुलाई में रिटेल कीमतें ऊंची रही हैं। और सखियायें जैसे उच्च खराब होने वाले उत्पादों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा, 'हाल की बात है कि मुख्य मुद्रास्फीति रीतिहासिक निचले स्तर पर है, जिससे संकेत मिलता है कि सामान्य तौर पर कीमतों का दवाव नहीं है। वृद्धि भी मजबूत बनी हुई है, इसके बाद मौद्रिक नीति में मुद्रा मुद्रास्फीति का 4 फीसदी लक्ष्य के करीब बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा।' एक अन्य अर्थशास्त्री ने कहा, वित्त

सोने और चांदी में आई नरमी

नई दिल्ली। घरेलू बाजार में आरबीआई को सोने और चांदी की कीमतें बढ़ी है। आज सोने के बावजूद भाव की सुर्ख-आती उछली रही पर इसके बाद दाम मिले लगे। वहीं चांदी के बावजूद भाव की सुर्ख-आती गिरावट के साथ हुई। सोने के बावजूद भाव 68,800 रुपये प्रति किलो के बावजूद भाव 79,400 रुपये के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना तेज सुर्ख-आती के बाद नीचे आया जबकि चांदी के बावजूद भाव की सुर्ख-आती भी कमजोर रही। सोने के बावजूद भाव की सुर्ख-आती आज बढ़त के साथ हुई पर बाद में इसके दाम नीचे आने लगे। मार्टी कर्मांडी एक्सचेंज (एपीसीएस) पर सोने का बेचमांक अक्टूबर कोनट्रैट आज 575 रुपये की तेजी के साथ 69,440 रुपये के भाव पर खुला। यह ने 69,440 रुपये के भाव पर दिन के उच्च और 68,740 रुपये के भाव पर दिन के निचला स्तर पर पहुंचा। सोने का बावजूद भाव इस साल 74,471 रुपये के भाव के शीर्ष स्तर पर पहुंचा। चांदी के बावजूद भाव की सुर्ख-आती कमजोर रही। एपीसीएस पर चांदी का बेचमांक सितंबर कोनट्रैट आज 283 रुपये की गिरावट के साथ 79,623 रुपये पर खुला। ये 79,478 रुपये के भाव पर दिन का उच्च और 79,338 रुपये के भाव पर दिन का निचला स्तर पर पहुंचा। इस साल चांदी के बावजूद भाव 96,493 रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोने के बावजूद भाव की सुर्ख-आती तेजी के साथ हुई। लेकिन बाद में इसके भाव गिर गए। चांदी के बावजूद भाव की सुर्ख-आती गिरावट के साथ हुई।

रुपए का आउटलुक बदला, आरबीआई ब्याज दरों को लेकर करेगा फैसला

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यों वाली मॉनेटरी पालिसी कमिटी (एपीसी) ब्याज दरों को लेकर अपने फैसले का ऐलान करेगी। भारतीय रुपए का आउटकूप पिछले महीने से बढ़ता है। ऐसा इतिहासिक क्योंकि आरबीआई ने इंडियन करेंसी को एक स्थितिदार दरों से रखने का प्रयास किया है। जानप के कैरी ट्रेड में अचानक लिक्विडिशन में उथल-पुथल के बाद वैश्विक बाजार में आई बड़ी गिरावट ने मंगलवार को रुपए को 83.96 प्रति डॉलर के लेवल पर धकेल दिया। आरबीआई ने मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच रेपो रेट में 2.5 फीसदी बढ़कर 6.5 फीसदी कर दिया था। इसके बाद से एपीसी ने पिछली आठ मॉनेटरी पालिसी में ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। आईएफएमआई और एनएसई के शेयरों में बढ़त रही। आरबीआई ने कहा कि फूड इन्फ्लेशन जोखिम को लेकर पालिसी का रुख सतर्क होगा। फीसदी में ब्याज दरों के कारण महंगाई के बढ़ने का दवाव बना हुआ है। रोजाना खाने-पीने की चीजों की कीमतों में संकेत मिलता है कि जुलाई में रिटेल कीमतें ऊंची रही हैं और सखियायें

बम्पर कमाई के बाद एलआईसी को फिर हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी में इस साल पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचने पर सरकार विचार कर रही है। केंद्र सरकार मई 2022 में इस कंपनी का आरबीआई लाई बिसके जरिए उसमें 21,000 करोड़ रुपए कायदा था। इस आरबीआई के तहत सरकार ने कंपनी में 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेची थी। एलआईसी में अभी सरकार की प्रीमियम के हिसाब से इसका बाजार हिस्सेदारी 58.87 फीसदी है। फेरिफे के हवाले से बताया गया है कि सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए एपीसीओ और क्यूआईपी लाने पर विचार कर रही है। कंपनी का शेयर सुर्ख-आती कारोबार में तीन फीसदी से ज्यादा तेजी के साथ 1116.95 रूपए पर ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी का बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार ने पिछले साल एलआईसी को इस शर्त को पूरा करने के लिए 1116.55 रूपए पर खूला। इसका इश्यू प्रारंभ 17 मई, 2022 को था। इसका बाजार कैप 7,03,497.87 करोड़ पर पहुंच गया है। सेबी नियमों के मुताबिक हर लिस्टेड कंपनी की 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए

